IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 1, February 2022

कोविड-19 का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉ ब्रजेश श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर – अर्थशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर चित्रकूट

शोध सारांश

कोविड-19 महामारी के कारण बहुत कम समय में दुनिया भर में तबाही मच गई है, जिससे लोगों की ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। स्वास्थ्य संकट, वस्तुओं की वैश्विक मांग और पूर्ति में कमी के साथ यह एक आर्थिक संकट में बदल गया। वैश्विक स्वास्थ्य संकट का भारत के स्वास्थ्य स्तर और अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक ज़रूरी नीति उत्तरदायित्व के तौर पर पूरे भारत में कड़े लॉकडाउन लगाए गए थे। नतीजतन, आर्थिक गतिविधियां लगभग रुक गई। क्योंकि काम की जगहें और विनिर्माण प्रक्रिया कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, इसलिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम हो गया। आपूर्ति श्रृंखला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इससे कुल मांग में गिरावट आई। इस प्रकार की अव्यवस्था ने अर्थव्यवस्था में विदेशी और वित्तीय क्षेत्र पर भी विपरीत असर डाला हैं।

मुख्य शब्द : COVID-19, लॉकडाउन, मांग तथा आपूर्ति , व्यवसाय

चीन के वुहान में कोरोना वायरस (covid-19) के पहली बार फैलने के बाद से, दुनिया कई तरह से बदल गई है। महामारी के भयानक असर, मौतों की संख्या और जूझ रहे स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली के अलावा, इस वायरस ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है I जहां अर्थव्यवस्था पर कोविड के कुछ असर थोड़े समय के लिए हैं, वहीं कई असर लंबे समय तक रह सकते हैं। लॉकडाउन ने आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन पर बहुत बुरा असर डाला है और GDP और आयात -निर्यात श्रृंखला पर नकारात्मक असर डाला है। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपने घरों को लौटे प्रवासी मज़दूरों की काफी मदद की। किन्तु Covid-19 की दूसरी लहर ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा कमज़ोरियों को बुरी तरह से उजागर किया है और उन्हें और खराब कर दिया है। कुछ ज़रूरी सेवाओं और गतिविधियों को छोड़कर, भारत की $2.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के दौरान बंद रही। दुकानें, खाने की जगहें, फैक्ट्रियां, परिवहन सेवाएं, व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद होने से लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था की गति पर बहुत बुरा असर पड़ा। अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र पर वैश्विक महामारी का सबसे बुरा असर पड़ा है। अगर अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए तो अप्रैल-जून के दौरान भारत की GDP में गिरावट 8% से ज़्यादा हो सकती है। निजी उपभोग और निवेश भारत की आर्थिक वृद्धि के दो सबसे बड़े इंजन हैं। खेती को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी बड़े क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। दूसरी लहर आने के बहुत पहले से ही भारतीय

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 1, February 2022

अर्थव्यवस्था मुश्किलों का सामना कर रही थी। कोविड-19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा असमानताओं को उजागर किया और उन्हें और खराब करने का कार्य किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे से पता चलता है कि 2021 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान बेरोजगारी दर में 7.9% से 12% की भारी बढ़ोतरी हुई है। MSMEs के अपने व्यवसाय बंद करने से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। लाखों नौकरियां हमेशा के लिए चली गई हैं और उपभोग कम हो गया है। सरकार को स्वास्थ्य संकट से लड़ने और कोविड-19 से शुरू हुई मंदी से आर्थिक पुनरुद्धार को तेज करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा । इस आपदा से निकलने का सबसे असरदार तरीका यह है कि सरकार अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर डाले , जो कि आसान नहीं है I

केंद्र के बिना किसी नोटिस के लॉकडाउन के जवाब में GDP ग्रोथ 23.9% गिर गई थी। 2020-21 में भारत की GDP 7.3% घट गई। आज़ादी के बाद किसी भी साल में भारतीय अर्थव्यवस्था का यह सबसे खराब प्रदर्शन था। लाकडाउन के कारण भारत की GDP वृद्धि दर 10 प्रतिशत से कम रहने की संभावना है।

Covid-19 की वजह से विभिन्न क्षेत्र पर प्रभाव

हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र :

चूँकि कई राज्यों ने स्थानीय लॉकडाउन लगाए हैं, इसलिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 2020 जैसा ही महसूस कर रहा है । हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में रेस्टोरेंट, बेड एंड ब्रेकफास्ट, पब, बार, नाइटक्लब और भी बहुत कुछ जैसे कई बिज़नेस शामिल हैं। भारत की सालाना GDP में जिस सेक्टर का बड़ा हिस्सा है, उसे राज्यों की पाबंदियों और कर्फ्यू से बहुत नुकसान हुआ है।

पर्यटन क्षेत्र :

हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा है। लाखों भारतीयों को नौकरी देने वाला यह क्षेत्र पहली लहर के बाद ठीक होने लगा था, लेकिन कोविड की दूसरी लहर तबाही मचाने के लिए वापस आ गई! पर्यटन क्षेत्र भारत की सालाना GDP में लगभग 7% का योगदान देता है।

इसमें होटल, होमस्टे जैसी और भी बहुत कुछ शामिल है। दूसरी लहर की वजह से लगी पाबंदियों ने पर्यटन क्षेत्र को कमज़ोर कर दिया है, जो पहले से ही वर्ष 2020 के कोरोना के पहली लहर से दबाव में था I

विमानन और ट्रैवल क्षेत्र :

महामारी की दूसरी लहर के दौरान विमानन और दूसरे क्षेत्र की कंपनियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बड़े ट्रैवल क्षेत्र पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। विमान और बड़े ट्रैवल क्षेत्र के लिए, इसकी पुनरुद्धार इस बात पर निर्भर करेगी कि भविष्य में लोग ऐसी सेवा चुनेंगे या नहीं। फिलहाल, विमानन और बड़े ट्रैवल क्षेत्र के लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। **ऑटोमोबाइल क्षेत्र :**

भारत में कोविड-19 की स्थिति के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जल्द ही दबाव रहने की उम्मीद है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 1, February 2022

रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर:

दूसरी लहर के दौरान रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में रुकावट आने लगी है क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर शहरी इलाकों को छोड़कर चले गए हैं। वर्ष 2020 तक इस क्षेत्र के लिए स्थिति गंभीर नहीं रही है।

राजकोषीय घाटा :

कोविड-19 महामारी ने हमारे राजकोषीय घाटा और विनिवेश लक्ष्य पर ज़्यादा असर नहीं डाला है। इस साल के केन्द्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 से 2022 के लिए 6.8% के राजकोषीय घाटा लक्ष्य की घोषणा की। 2020-21 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 9.5% हो गया, जबकि पहले 3.5% का अनुमान लगाया गया था। हमारी वित्त मंत्री ने पिछले कुछ सालों में बढ़े हुए कर अनुपालन और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के ज़रिए बढ़ते कर आय को बढ़ाकर 2025-26 तक GDP का 4.5% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करने का वादा किया है। फरवरी 2020 में सरकार ने जो मध्यम- अवधि राजकोषीय नीति व्यक्तव्य पेश किया था, उसके मुताबिक 2021-22 और 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा क्रमशः 3.3% और 3.1% था।

लॉकडाउन और पाबंदियों का असर:

पहले जिस हद तक स्थानीय लॉकडाउन और पाबंदियां लगाई गई हैं, उससे आर्थिक पुनरुद्धार पर लगने वाले समय पर असर पड़ा है। पूरे साल लगातार राजकोषीय उत्प्रेरणा की गुंजाइश है। कुछ हद तक, अगर व्यवसाय को कम कम ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, तो मौद्रिक उत्प्रेरणा भी संभव है। दूसरी लहर ने भारत की नाजुक आर्थिक पुनरुद्धार को काफी नुकसान पहुचाया है। बढ़ती असमानता और घरेलू बैलेंस शीट पर दबाव ने पुनरुद्धार को रोक दिया है। 2019-20 में सिर्फ 4% की वृद्धि से लेकर 2020-21 में 7-8% की गिरावट और 2021 में पुनः झटके के कारण भारत लगभग पूरी तरह से रुक गया है। इसलिए, राजकोषीय नीति को कमजोर व्यवसाय को आर्थिक रिकवरी की ओर ले जाने के लिए भरपूर वित्तीय मदद करनी होगी ।

रिकवरी का रास्ता क्या है?

अगर समय के साथ आउटब्रेक और बिगड़ता है, या अगर केस नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे भारत की आर्थिक और राजकोषीय रिकवरी का जोखिम बढ़ जाएगा। कोविड की लहरें कम होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी रिकवरी फिर से शुरू करनी चाहिए और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में प्रति व्यक्ति आय के अपने जैसे स्तर पर अपने साथियों की तुलना में तेज़ रफ़्तार से बढ़ती रहेगी। दूसरी तरफ, सरकारी आय में उतनी अधिक रिकवरी नहीं होगी और गंभीर गिरावट की स्थिति में अतिरिक्त राजकोषीय खर्च करना पड़ सकता है। कमोडिटीज़ और ऑटोमोबाइल सेक्टर संक्रमण

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 1, February 2022

के शुरुआती दौर और उससे जुड़े लॉकडाउन के उपायों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जुलाई 2021 के बाद इसमें अच्छी रिकवरी हुई।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी ने इस बात की संभावना कम कर दी है कि 2020 जैसी कीमतों में भारी गिरावट फिर से होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में दबी हुई मांग शायद 2020 की पूर्व पाबंदियों में ढील दिए जाने पर एक मज़बूत रिकवरी लाएगी। कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारतीय आधारसंरचना के लिए एक मज़बूत रिकवरी को चुनौती दी है। जैसे-जैसे उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने की कोशिश कर रहे हैं, नियमित प्रतिफल और मांग में तेज़ी से रिकवरी की वजह से अधिक आय प्राप्त करते रहेंगे। यदि सरकार गतिशीलता पर पाबंदियों को और बढ़ाती है, तो इससे घरेलू रिकवरी में रुकावट आ सकती है। वर्ष 2020 के खराब प्रदर्शन के बाद एक मजबूत रिकवरी की ज़रूरत है। जैसे-जैसे बीमारी का प्रकोप बढ़ता गया, राज्य सरकारों ने पाबंदी वाले लॉकडाउन के उपाय लागू किए, जिससे उभरती हुई आर्थिक रिकवरी रुक गई।

वैक्सीनेशन की धीमी रफ़्तार भारत की आर्थिक रिकवरी पर बोझ बन सकती है। भारत में कई क्षेत्र में रिकवरी ज़ोरदार रही है, खासकर राजकोषीय वर्ष 2021 की आखिरी तिमाही में। घरेलू विमान परिवहन पर रोक और अन्तराष्ट्रीय ट्रैवल में कमी ने निर्यात की रिकवरी को खत्म कर दिया है। कोविड की लहर ने छोटे और मध्यम आकार के उद्यम को खास तौर पर बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता में रिकवरी में देरी हुई है। गतिशीलता , सामान्य स्तर के 50-60% तक कम हो गई है। इसलिए, लोग ज़्यादा घर पर रह रहे हैं और कम खर्च कर रहे हैं। इस साल के आखिर में रिकवरी शुरू हो जाएगी। मार्च में भारत की उभरती हुई आर्थिक रिकवरी ने सरकारी राजस्व को मज़बूत किया।

ऊर्जा क्षेत्र : भारतीय ऊर्जा क्षेत्र बहुत ज़्यादा आय सृजित करेगा और यह भारत की GDP की रिकवरी को प्रेरित करेगा।

विमानन क्षेत्र : दूसरी लहर ने भारत के एयर रिकवरी ट्रैफिक को नुक्सान में डाल दिया है। घरेलू पैसेंजर ट्रैफिक कोविड से पहले के लेवल से 75% कम हो गया है। सबसे खराब हालत में ट्रैफिक रिकवरी अनुमान से 10% कम हो सकती है। कमज़ोर ट्रैफिक से एयरपोर्ट के नकद प्रवाह पर असर पड़ता है। थोड़ी रुकावट के बाद सड़क परिवहन में तेज़ रिकवरी होगी।

पोर्ट: आयात मात्रा में मामूली रिकवरी देखी जाएगी । उर्वरक , कच्चा तेल और कोयला कि मांग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे।

राजकोषीय वर्ष 2022 में नकद हानि कुल लोन का 2.2% रहेगा, जिसके बाद यह 2023 में 1.8% पर रिकवर हो जाएगा। भारत की मज़बूत आर्थिक रिकवरी और आर्थिक संकट के असर को कम करने के लिए केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से बैंकों पर बोझ कम हुआ है। इसके अलावा, बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को मज़बूत करने के लिए पूंजी को जुटाया है। इससे कोविड से जुड़े नुकसान की मार कम होगी। कमज़ोर उपभोग के साथ बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने और औपचारिक क्षेत्र में वेतन में कटौती से बैंकिंग क्षेत्र के लोन और 'क्रेडिट कार्ड' लोन पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही बैंक के गैर – निष्पादित परिसंपत्तियों में रिकवरी रेट भी कम हुई है।

पिछले साल, सरकार ने रोजी-रोटी के बजाय ज़िंदगी को चुना । आर्थिक सुधार के लिए पहला खतरा क्षेत्रीय मामले हैं, जिनकी वजह से लॉकडाउन को और बढ़ाया जा रहा है और इसलिए वे आर्थिक सुधार की रफ्तार को सीमित कर रहे हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 1, February 2022

दूसरा खतरा वैक्सीन आपूर्ति से होने वाले वैक्सीनेशन दर हैं। हमारी श्रम बल के एक बड़े हिस्से को टीका लगाए बिना, यह खतरा है कि वायरस हमारी असली अर्थव्यवस्था को बाधित कर देंगे। यह कोविड-19 के दुनिया भर के मामलों से साफ़ है।

निष्कर्ष

अंततः अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान मौजूदा अनुमानों से कहीं अधिक गंभीर होने की संभावना है। मांग पक्ष पर, सरकार को आवश्यक आय सहायता और राजकोषीय स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से बचाने के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। अब तक जो संतुलन बना है वह उचित प्रतीत होता है, लेकिन सरकार को गरीबों की आय बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। आगे की राजकोषीय पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य और स्थानीय सरकारों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण हो सकती है। नीति निर्माताओं को घटनाक्रम के अनुसार प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों पर झटके के प्रभाव को कम किया जा सके और सतत आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। साथ ही, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिक्रियाएं नियमों पर आधारित ढांचे में ही रहें और मनमानी के प्रयोग को सीमित किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सके।

सन्दर्भ

[1]. Arundhati Roy,B.C.M.Patnaik,I.S.(2020). Impact of Covid-19 Pandemic on Indian MSME Sector. Eurasian Chemical Communications, 2(6), 991–1000
[2]. Gupta, A. (2020b). India: Coronavirus (COVID-19) and Indian Economy. Mondaq. https://www.mondaq.com/india/operational-impacts-and-strategy/936014/coronavirus-covid-19-andindian-economy.
[3]. Mehta, B., & Arjun, K. (13th April 2020). COVID-19 and The Lockdown Impact: Estimating the Unemployment and Job Losses in India's Informal Economy, The Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/red-button-day-light/covid-19-and-the-lockdown-impact-estimating-theunemployment-and-job-losses-in-indias-informal-economy/
[4]. Goyal, S. (2020), "What is the impact of coronavirus on Indian economy?", available at: www.jagranjosh.com/general-knowledge/what-is-the-impact-of-coronavirus-on indianeconomy1582870052-1
[5]. Accessed on 13 April 2020 A. Abiad, R.M. Arao, S. Dagli The Economic Impact of the COVID-19 Outbreak on Developing Asia (2020), 10.22617/BRF200096